

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-९
संख्या-२०१५/XXVII(९)/य०आ०-०५/स्टाप्प/२०१५
देहरादून: दिनांक: २९ अक्टूबर, २०१५

अधिसूचना / आदेश

राज्यपाल, भारतीय स्टाप्प अधिनियम, १८९९ (केन्द्रीय अधिनियम राख्या २ वा १८९९) की घारा ९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उद्यम स्थापना हेतु राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू-स्वामियों से उनकी भूमि हीज पर लेने अथवा क्षय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निम्नचन में प्रभार्य स्टाप्प शुल्क में उत्तराखण्ड स्थान, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, २०१५ में वर्णित प्राविधिकानुसार छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त छूट उद्यम स्थापना रो इतर उपयोग में लागू नहीं होगी।

(अमित सिंह नंगी)
सचिव।

संख्या- २०५ (१) / २०१५/XXVII(९)/य०आ०-०५/स्टाप्प/२०१५ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

१. निजी साधेव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव गहोदय के राख्यानाथ प्रेषित।
२. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
३. गम्भलायुक्त, कुगायू एवं गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
४. महानिरीक्षक, नियन्यन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
५. तमस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
६. जमीन सहायक महानिरीक्षक, नियन्यन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
७. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इसे आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गुजट के भाग-४ खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी १०० प्रतियां वित्त अनुभाग-९ में उपलब्ध करा दें।
८. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

१२
(बी०डी० बलवाल)
अनुसंचित।